Use of fish finders and Echo Sounders in Marine fisheries

4057. SHRI A. NEELALOHITHADASAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Union Government are aware of the beneficial uses of fish finders and Echo Sounders in Marine fisheries;

(b) whether the Marine Product Export Development Authority has any scheme in hand or in contemplation to supply the above instruments at subsidised rates to actual fishing Vessels; and

(c) if so, details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

अजमेर, राजस्थान में स्विटजरलैण्ड की सहायता से बकरी पालन केन्द्र

4058. **श्री भगवान देव** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के अजमेर जिले मे स्विटजरलैण्ड की सहायता से एक बकरी पालन केन्द्र खोले जाने की कोई योजना मंजूर की है ;

(ख) यदि हा, तो इस योजना पर केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा कितना-कितना अनुमानित व्यय किया जाएगा ;

(ग) यह केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा; और

(घ) केन्द्र में कितनी बकरियों के पाले जाने की व्यवस्था की जाएगी और इस केन्द्र से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) तथा (ख). सरकार इस योजना पर विचार कर रही है।

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही नही होता।

उल्हास नगर, महाराष्ट्र स्थित मानव चालित टेलीफोन केन्द्र का कार्यकरण

4059 **श्री भगवान देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उल्लास नगर, जिला थाना महाराष्ट्र के निवासियों से मानव चालित टेलीफोन केन्द्र के कार्यकरण के बारे में शिकायत मिल रही हैं और क्या उनकी मांग है कि वहां इसके स्थान पर स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना की जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या इस टेलीफोन केन्द्र के स्थान पर स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(घ) यदि हा, तो इस टेलीफोन की स्थापना कब और कहां की जायेगी ; और

(ङ) यदि नही, तो इसकी स्थापना मे क्या बाधाएं हैं और किसने नगर में ऐसा टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का मापदण्ड क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हा।

(ख) और (ग). स्वचल एक्सचेंज द्वारा हस्तचालित एक्सचेज के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि उल्लास नगर में टेलीफोन प्रणाली कार्यकरण ठीक है, फिर भी महाप्रबंधक दूरसंचार की सेवा और अविलम्ब निराकरण उपायों को प्रारम्भ करने के सभी मामलों के सम्बन्ध में जांच करने के निदेश दे दिये गए है।

(घ) इस उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थानातरित भूखण्ड संख्या 705, भाग 7 बी०, कैम्प सख्या 2 के भूखण्ड मे इस एक्सचेज को 1984 तक सेवा योग्य बनाए जाने की संभावना है।

(ङ) प्रश्न ही नही उठता।

सिंधी भाषा का विकास प्रचार

4060. **श्री भगवान देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सिंधी भाषा के विकास प्रचार के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है और इस सम्बन्ध में कौन सी योजनाएं क्रियान्वित करने का विचार है ;

(ख) सिंधी भाषा के विकास के लिए अब तक क्रियान्वित की गई योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सिंधी भाषा विकास बोर्ड में ऐसे कितने पदाधिकारी और कर्मचारी हैं जो सिंधी भाषी हैं और उनकी संख्या कितनी है जो गैर-सिंधी भाषी हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सिंधी भाषा के विकास के लिए 3.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। सिंधी-पुस्तक निर्माण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत शैक्षणिक साहित्य और सामान्य पुस्तकें तथा संदर्भ कृतियां प्रकाशित करने का प्रस्ताव है। दो संदर्भ कृतियां प्रकाशित की जा चुकी हैं और बच्चों की पांच पुस्तकें छप रही हैं। अनुवाद के लिए कई पुस्तकें तथा पुनर्मुद्रण के लिए दुर्लभ पुस्तकें चुनी गई है। एक सिंधी शब्द-कोश को तैयार किया जा रहा है। सिंधी लेखकों को प्रोत्साहित करने हेतु उत्कृष्ट सिंधी पुस्तकों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार योजना और नये सिंधी लेखकों के लिए कार्यशालाओं के आयोजन तथा साहित्यिक महत्व की चुनी हुई सिंधी पुस्तकों को काफी मात्रा में खरीदने की एक योजना शुरू की गई है।

(ग) इस प्रकार का कोई सिंधी भाषा विकास बोर्ड नहीं है। तथापि, सिन्धी पुस्तक निर्माण योजना को एक सिन्धी अध्येता सलाहकार समिति की देखरेख में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें दो सरकारी सदस्य तथा 10 गैर-सरकारी सदस्य हैं। सभी गैर-सरकारी सदस्य सिन्धी भाषी हैं। यह योजना वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जहां दो अधिकारी इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं जिसमें एक सिन्धी है तथा दूसरा गैर-सिन्धी है।

Violation of building law in East of Kailash Community Shopping Centre

4061. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some plot-holders of multi-storeyed buildings in the East of Kailash Community Shopping Centre of Delhi Development Authority put up mezzanine floors in violation of the approved plan of the Delhi Development Authority thus resulting in increased covered area and extra rental income;

(b) if so, their particulars and the circumstances under which Completion Certificates were issued to them;

(c) the manner in which this violation has been regularised and how the penalty levied keeping in view the permanent rental income accruing from such unauthorised additions; and

(d) the amount of penalty levied in each case before issuing the completion certificates?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI P. C. SETHI): (a) The DDA has intimated that plot owners in the multi-storyed buildings in the East of Kailash Community Shopping Centre of DDA have constructed mezzanine floors in excess of the permissible limits.

(b) A recent survey conducted by the DDA has revealed that in 32 cases, violations have come to light. Completion Certificates have not been issued to them.

(c) and (d). These violations have not been regularised. Show cause notices have been issued to the defaulters.

Death of Staff in service in Bihar Postal Circle

4062. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) total number of death of staff of all categories while in service during 1977-78, 1978-79 and 1979-80 in Bihar Postal Circle;

(b) total number of applications received for appointment in relaxation of normal rules during the aforesaid period;

(c) total number of appointments made in relaxation of normal rules during the aforesaid period;

(d) total number of cases in which such applications have been rejected during the above period;